दैनिक
# स्वर्णिम प्रदेश
PRN: MCN/329/2025-2027
epaper.swarnimpradesh.in
संरक्षक: मां वैष्णो देवी

**विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें**
अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो दैनिक स्वर्णिम प्रदेश आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनी नोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।
**ईमेल: swarnimpradesh@yahoo.com**
**या वाट्सऐप नं. 8898271111**

वर्ष : 8 • अंक : 239 • मुंबई, शनिवार 7 मार्च, 2026 • पृष्ठ : 6 • मूल्य: 2 रुपये • संपादक : सुनील कुमार तिवारी • Email: swarnimpradesh@yahoo.com www.swarnimpradesh.in

## निर्यात आधारित खेती से किसानों की आमदनी में होगा इजाफा: पीएम मोदी

संवाददाता

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में निर्यात आधारित कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए और उसे वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ा जाए। इससे नए रोजगार पैदा होंगे और किसानों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने 'कृषि और ग्रामीण परिवर्तन' विषय पर आयोजित पोस्ट-बजट वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार और एक रणनीतिक स्तंभ है।

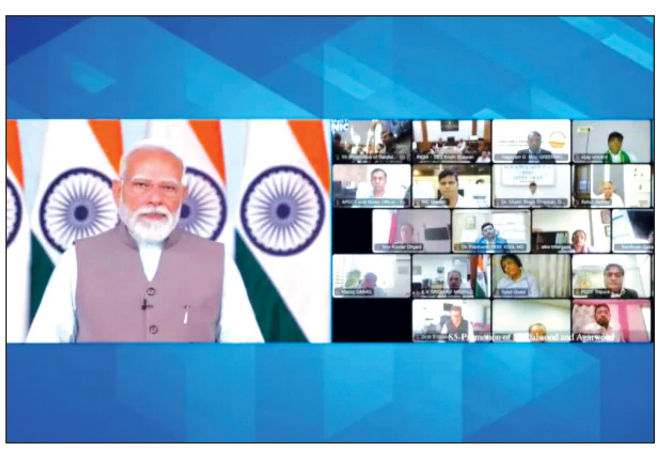

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की दूसरी तिमाही की शुरुआत हो चुकी है और हमें कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करना होगा। वैश्विक मांग तेजी से बदल रही है, इसलिए अब चर्चा निर्यात आधारित खेती, फसल विविधीकरण और नई तकनीकों के इस्तेमाल पर केंद्रित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए कई अहम सुधार किए गए हैं। उन्होंने कृषि विशेषज्ञों, उद्योग जगत और किसानों से मिलकर काम करने की अपील की ताकि उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि विशेषज्ञ, उद्योग और किसान मिलकर काम करें ताकि भारत वैश्विक बाजार से बेहतर तरीके से जुड़ सके। इसके साथ ही उन्होंने गुणवत्ता और ब्रांडिंग मानकों को बढ़ावा देने की भी जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात भी कही और कहा कि इससे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन भी भविष्य में एक बड़ा निर्यात आधारित क्षेत्र बन सकता है। ग्रामीण समृद्धि के लिए नए बिजनेस मॉडल और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। पीएम मोदी ने काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम, अखरोट और पाइन नट्स जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की संभावनाओं को भी उजागर किया। उन्होंने पशुपालन और तटीय मत्स्य क्षेत्र में निजी निवेश और उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए एसएचई-मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के विस्तार की भी बात कही। उन्होंने बताया कि भारत ने कृषि के लिए एक बड़ा डिजिटल आधार तैयार किया है, जिसके तहत 7.63 करोड़ से ज्यादा किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 23.5 करोड़ फसल प्लॉट का सर्वे किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भी उच्च मूल्य वाली खेती, कृषि से जुड़े क्षेत्रों और तकनीक आधारित खेती पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजन और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कई लक्षित कदमों की घोषणा की है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 1,51,853 करोड़ रुपए से करीब 7 प्रतिशत अधिक है। यह किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने पर सरकार के लगातार फोकस को दर्शाता है। बजट 2026-27 में तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की योजना है ताकि किसानों की आय बढ़ सके। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगरवुड और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट्स की खेती को भी समर्थन दिया जाएगा।

## इतिहास से सीखकर ही देश का भविष्य मजबूत होता है: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

संवाददाता

**कोलकाता।** पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित ₹मैरीटाइम कॉन्क्लेव सागर संकल्प₹ में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, ₹पश्चिम बंगाल की धरती की अलग ऊर्जा है। इस भूमि ने एक तरफ भारत को साहित्य और कला दिया और दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनल प्राइड को भी दिशा दी है। एक समय था कि जब समुद्री रास्ते से कोई वस्तु आती थी तो कोलकाता केंद्र हुआ करता था। हुबली के किनारे बसा ये शहर के देश के आर्थिक मजबूती का साक्षी रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया केवल सूचना देना का माध्यम नहीं है बल्कि समाज को एक दिशा भी देता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भारत के गौरवशाली इतिहास पर ध्यान देते हैं तो कई सारी बातें पता चलती हैं। ढाई हजार साल पहले से लेकर मध्यकालीन तक भारत ग्लोबल ट्रेड का प्रमुख सेंटर रहा है। उन्होंने कहा कि उस समय जब दुनिया के कई हिस्से विकास के प्रारंभिक अवस्था में थे तब भारत ज्ञान, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा था। उस समय भारत के जहाज समुद्री मार्गों से दूर-दूर तक यात्रा करते थे। हमारा संपर्क रोमन एंपायर और मेसबटोमिया सभ्यता तक स्थापित था। उस समय श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक भारतीय व्यापारियों और समुद्री यात्रियों की पहुंच थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र की अहमियत को ध्यान में रखते हुए, यह ज़रूरी है कि हम अपने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक को साथ लेकर आगे बढ़ें। जो राष्ट्र अपने इतिहास से प्रेरणा लेता है, वही भविष्य को आत्मविश्वास के साथ मज़बूती देता है। आज समुद्री क्षेत्र पहले की तुलना में, काफी बदल चुका है। आज के समय में समुद्री क्षेत्र सिर्फ़ व्यापार के रास्ते या नौसैनिक ताकत तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, तकनीकी इनोवेशन और रणनीतिक स्वायत्तता का अहम आधार बन चुका है। रक्षा क्षेत्र में आज हाई एंड और सटीक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार की शुरू से सोच रही है कि इस अनिश्चितता के दौर में सप्लाई चेन में रुकावटों से बचने का एक ही उपाय 'आत्मनिर्भरता' है। हमारी आत्मनिर्भरता के विज़न की एक प्रमुख धुरी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। अब पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, प्रदर्शन बेंचमार्किंग और आर एंड डी पर खास ज़ोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा, भारत के रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता रही है। पहले ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने रक्षा निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

## 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा : गृहमंत्री अमित शाह

संवाददाता

**भुवनेश्वर।** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों और केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण देश अब इस समस्या से मुक्ति के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कटक के मुंडुली में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र सरकार देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि 31 मार्च तक भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।" शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों के समन्वित और लगातार अभियानों के कारण देश अब दशकों पुरानी इस समस्या से छुटकारा पाने की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तय समयसीमा के भीतर नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सीआईएसएफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। शाह ने कहा, "चाहे ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना , नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सीआईएसएफ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।" उन्होंने तथाकथित "रेड कॉरिडोर" की अवधारणा पर भी प्रहार करते हुए कहा कि सुरक्षा बल उन लोगों को पूरी तरह परास्त कर देंगे जो तिरुपति से पशुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देखते हैं। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारे सुरक्षा बल इस चुनौती को पूरी तरह समाप्त कर देंगे, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी।

## सीएम फडणवीस ने पेश किया महाराष्ट्र का बजट 2026-27

संवाददाता

**मुंबई।** महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद चौंकाने वाले और गौरवपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और बजट का आकार अब दुनिया के कई विकसित यूरोपीय और एशियाई देशों से भी बड़ा हो गया है। उनके अनुसार, यदि महाराष्ट्र को एक राष्ट्र के रूप में देखा जाए, तो वह अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में विश्व स्तर पर 30वें स्थान पर आता है। यह आंकड़ा न केवल राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि इसे भारत के विकास का असली 'पावरहाउस' भी साबित करता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र का सकल

राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) अब 51 लाख करोड़ रुपये (लगभग 566-610 बिलियन डॉलर) के स्तर को छू रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने रेखांकित किया कि महाराष्ट्र का बजट आकार और आर्थिक गतिविधियां अब ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और ग्रीस जैसे सैकड़ों देशों से कहीं अधिक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य का लक्ष्य महज आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि 2047 तक 'विकसित महाराष्ट्र' के सपने को साकार करते हुए इसे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। देवेंद्र फडणवीस के दावों के अनुसार, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विस्तार इतनी तेजी से हुआ है कि इसने ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हंगरी, पुर्तगाल और डेनमार्क जैसे समृद्ध देशों को पीछे छोड़ दिया है।

## सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट क्रैश में दोनों पायलटों की मौत

संवाददाता

**कार्बी आंगलोंग।** असम के कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाके में गुरुवार देर शाम को सुखोई-30 एमकेआई फाइटर एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से दोनों पायलटों की मौत हो गई। दोनों की पहचान स्क्वाड्रन लीडर अनुज और को-पायलट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर के रूप में हुई है। लेफ्टिनेंट पूर्वेश आईएएफ के फ्लाइंग नेविगेटर थे। हादसे की आधिकारिक जानकारी आईएएफ ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी है। दुर्घटना स्थल से दोनों वायु सैन्य कर्मियों के शव मिल गए हैं।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की एक्स पोस में भारतीय वायु सेना ने स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुर्वेश दुरागकर के निधन की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि दोनों को सुखोई-30 दुर्घटना में घातक चोटें आईं। आईएएफ ने कहा है कि इस हादसे पर भारतीय वायु सेना के समस्त कर्मी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और इस शोक के समय दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। ह य हादसा गुरुवार रात लगभग 7 बजे के आसपास हुआ। विमान से संपर्क टूटने के बाद जोरहाट वायुसेना की टीम ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। हादसास्थल पर वायु सेना की टीम को पहुंचने में लगभग चार घंटे का समय लगा। हालांकि, हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया गया है कि जोरहाट से टेक-ऑफ करने के कुछ ही देर बाद प्लेन कार्बी आंगलोंग जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। जोरदार आवाज सुनकर आसपास के गांवों के लोगों में डर फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

## विदेश नीति पर राहुल गांधी का आरोप, बोले- सरकार समझौतावादी रवैया अपनाती है

संवाददाता

**नई दिल्ली।** लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की है। राहुल गांधी के आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर 11 फरवरी को लोकसभा में दिए गए भाषण का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया है, भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और सत्य एवं अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं, वह नीति नहीं है। यह एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। राहुल गांधी ने जो वीडियो पोस्ट किया है, उस

पर लिखा है, 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में विपक्ष के नेता ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के खतरे में होने की चेतावनी दी। अमेरिका ही तय करेगा कि हम किससे तेल खरीद सकते हैं और किससे नहीं। चाहे रूस से खरीदना हो या ईरान से, अमेरिका ही फैसला करेगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फैसला नहीं करेंगे। एक दिन पहले 5 मार्च को भी राहुल गांधी ने कहा था, विश्व एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है। आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है, क्योंकि हमारे आयात का 40 फीसदी से अधिक हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी के लिए स्थिति और भी बदतर है। संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है, हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है। फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो समझौतावादी हैं और रणनीतिक स्वायत्तता को त्याग दिया है। हालांकि पिछले सप्ताह इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक उछाल देखा गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

## हस्तशिल्प क्षेत्र में विविधीकरण पर जोर: गिरिराज सिंह

संवाददाता

**कोलकाता।** केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कोलकाता में जूट, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों से जुड़े अधिकारियों और हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पारंपरिक वस्त्र उद्योगों को नवाचार, विविधीकरण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से मजबूत बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

बैठक में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के अधिकारी, क्षेत्रीय वस्त्र मंत्रालय के कार्यालयों के प्रतिनिधि, जूट बोर्ड, जूट और संबद्ध रेशा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान तथा भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ सहित कई संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि जूट क्षेत्र तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसमें विविध तथा उच्च मूल्य वाले उत्पादों का विकास हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने जूट आधारित कपड़े से बनी एक जैकेट और शॉल भी धारण किया, जो जूट उद्योग द्वारा विकसित विशेष कपड़े से तैयार किया गया है। इस कपड़े में 60 प्रतिशत जूट के साथ कपास और विस्कोस रेशा मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से जूट का उपयोग मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री जैसे थैलों तक सीमित था, लेकिन अब यह क्षेत्र फैशन परिधान और आधुनिक वस्त्र उत्पादों तक विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जूट आधारित कपड़ों और नए प्रकार के प्राकृतिक रेशों के विकास से किसानों, कारीगरों और उद्योग से जुड़े लोगों को अधिक मूल्य मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जूट और अन्य प्राकृतिक रेशों में प्रौद्योगिकी अपनाने, नवाचार और विविधीकरण को बढ़ावा देने से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। इससे बुनकरों, कारीगरों और जूट किसानों को सशक्त बनाने के साथ भारतीय पारंपरिक वस्त्र क्षेत्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हथकरघा, हस्तशिल्प और जूट जैसे क्षेत्र देश भर में लाखों कारीगरों और श्रमिकों के लिए रोजगार और आय सृजन के बड़े स्रोत बन सकते हैं। बैठक में इन क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान, बाजार विस्तार और उत्पाद विविधीकरण को आगे बढ़ाने के उपायों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से जूट का उपयोग मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री जैसे थैलों तक सीमित था, लेकिन अब यह क्षेत्र फैशन परिधान और आधुनिक वस्त्र उत्पादों तक विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जूट आधारित कपड़ों और नए प्रकार के प्राकृतिक रेशों के विकास से किसानों, कारीगरों और उद्योग से जुड़े लोगों को अधिक मूल्य मिलेगा।

# संपादकीय

## डब्लूएचओ की वैश्विक प्रासंगिकता पर उठे सवाल

विश्व स्वास्थ्य संगठन से यूएस के हटने के बाद डब्लूएचओ की वित्तीय स्थिरता और ग्लोबल हैल्थ लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं तथा इसकी संरचनागत कमजोरियाँ उजागर हुई हैं। यूएस के हटने से डब्लूएचओ की फडिंग को होगा खतरा, जिससे सुधार, एफिशियंसी और जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत ग्लोबल साउथ में एक मुख्य शक्ति है, जिसे डब्लूएचओ और स्थानीय स्वास्थ्य नीतियों के तालमेल और दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। नई दिल्ली। हाल ही में यूएस के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग तथा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) से यूएस का नाम वापस लिए जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी। यूएस ने अपना नाम इसलिए वापस लिया क्योंकि डब्लूएचओ के सदस्य देशों के अनुचित राजनैतिक प्रभाव से संगठन खुद को स्वतंत्र रखने में असमर्थ पाया गया। इसके बाद पूरे विश्व के देश अब यह आकलन कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए घरेलू डिसीज़न मेकिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य फ्रेमवर्क का क्या प्रभाव होगा। ग्लोबल हैल्थ सिस्टम में अक्सर राष्ट्रीय संदर्भों को नजरंदाज किया जाता है, एक फ्लेक्सिबल पॉलिसीमेकिंग संभव नहीं हो पाती है तथा नतीजों के बजाय सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाती है। बदलाव के इस दौर में भारत के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अपनी लंबी परंपरा पर पुनर्विचार करने का अवसर है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से स्थानीय प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेकर जन-स्वास्थ्य में एक मजबूत नेतृत्व पेश किया है। स्थानीय स्तर पर बनाई गई किफायती जेनेरिक दवाओं से एच.आई.वी/एड्स के इलाज का विस्तार करने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियानों में से एक के लिए कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्रियान्वयन करने तक भारत ने एक स्वस्थ राष्ट्र का ब्लूप्रिंट सफलतापूर्वक तैयार किया है। डोनर की प्राथमिकताओं से ग्लोबल पॉलिसी किस प्रकार आकार ले सकती हैं, इसका एक मुख्य उदाहरण तम्बाकू नियंत्रण है। 20 जनवरी, 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने डब्लू.एच.ओ से बाहर होने के यूएस के प्लान की घोषणा की थी। इस एक साल लंबी प्रक्रिया के दौरान डब्लूएचओ को अपने सबसे बड़े डोनर से फंड मिलना बंद हो गया। इससे ब्लूमबर्ग फिलॉन्थ्रोपीज़ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी समाजसेवी संस्थाओं को आगे आकर विशेष हैल्थ एजेंडा में अपना सहयोग देने का अवसर मिला। प्रभाव के एक तरफ झुकाव से एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ग्लोबल फ्रेमवर्क ग्लोबल साउथ की विभिन्न जरूरतों का प्रतिनिधित्व ठीक से करते हैं या नहीं। भारत में तम्बाकू की पॉलिसी से प्रदर्शित होता है कि ये ग्लोबल असंतुलन क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं। भारत में तम्बाकू का सेवन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, जो सबसे अधिक विस्तृत तम्बाकू उत्पादों की सेवन करती है। यहाँ पर 267 मिलियन से अधिक यूज़र्स हैं, जिनमें से अधिकांश धूम्ररहित और असंगठित क्षेत्र के उत्पादों पर निर्भर हैं। पिछले दशक में भारत में डब्लूएचओ के फ्रेमवर्क में तम्बाकू नियंत्रण की नीतियों को अपनाया गया, जो स्थानीय स्तर पर प्रमाण आधारित न होकर बाहरी प्रभावों के अनुरूप थीं। डब्लूएचओ का अनुपालन करने के लिए भारत ने साल 2019 में प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट (पेका) के तहत सिगरेट के विकल्पों को प्रतिबंधित कर दिया। यह निर्णय लेने से पहले इस मामले में न तो कोई घरेलू अध्ययन किया गया और न ही तुलनात्मक जोखिमों का आकलन किया गया। इन उत्पादों के मामले में प्राप्त होने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रमाणों को भी नजरंदाज कर दिया गया। नतीजा यह निकला कि भारत में सिगरेट का सेवन करने वाले व्यस्क लोगों को रैगुलेटेड, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित विकल्प उपलब्ध नहीं हो पाए, और उन्हें कम नुकसान वाले ओरिज़नल उत्पादों को चुनने की स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ा। इस कमी ने गैरकानूनी बाजारों को बढ़ावा दिया, तथा जन स्वास्थ्य को सबसे निचले पायदान में पहुँचा दिया। डॉ. लैंसेलॉट मार्क पिंटो, पल्मोनोलॉजिस्ट एवं एपिडेमियोलॉजिस्ट कंसल्टैंट, पी.डी हिंदुजा हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर ने कहा, ''हैल्थ पॉलिसी को डेटा पर आधारित होना चाहिए, जो स्थानीय रूप के अनुकूलित, किफायती और सामाजिक नियमों के अनुरूप हो। ओआरएस जैसे सरल से उपाय ने फार्मा लॉबी या हितधारकों के बिना ही जितनी जानें बचाई हैं, उतनी जानें कई दवाईयों ने मिलकर नहीं बचाई हैं। यह इस बात का एक मजबूत उदाहरण है कि स्थानीय समाधानों को प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए। सीधा प्रतिबंध सिगरेट का सेवन करने वालों को कम नुकसान वाले विकल्पों से वंचित करता है। इसलिए विज्ञान के लिहाज से यह ठीक नहीं है। अब इस दिशा में फंड और डब्लूएचओ के दिशानिर्देशों की कमी होगी, इसलिए हमारे पास स्थानीय शोध को बढ़ाने और शोध के नतीजों के आधार पर पॉलिसी बनाने का अवसर है।

# एआई रोबोट से नहर की सफाई

**संवाददाता**

**नई दिल्ली।** स्वच्छ भारत मिशन–अर्बन 2.0 के तहत तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने शहरी स्वच्छता में बड़ा कदम उठाते हुए एआई-संचालित जी-स्पाइडर रोबोट को नहरों की सफाई के लिए तैनात किया है। यह रोबोट बिना मानव हस्तक्षेप के खतरनाक और कठिन इलाकों में सुरक्षित तरीके से कचरा हटाने में सक्षम है।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन के पास अमायिझंचन नहर का हिस्सा लंबे समय से सफाई के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां ऊंचाई कम होने, लगातार पानी बहने और सुरक्षित प्रवेश बिंदु न होने के कारण पारंपरिक तरीकों से सफाई करना बेहद कठिन था। इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश ने जी-स्पाइडर रोबोट का उद्घाटन किया। यह पहल नगर निगम और टेक्नोपार्क स्थित जेनरोबोटिक इनोवेशंस के सहयोग से हुई है, जो पहले 'बैंडिकूट' नामक रोबोटिक स्कैवेंजर विकसित कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस रोबोट के इस्तेमाल से सफाईकर्मियों को खतरनाक और अस्वच्छ वातावरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई-सक्षम विज़न और सेंसर तकनीक से लैस यह रोबोट नहर में जमा विभिन्न प्रकार के कचरे को पहचान कर सुरक्षित तरीके से हटाता है। इसमें बायोमिमेटिक क्लॉ ग्रैबर लगा है जो मिश्रित और अनियमित मलबे को पकड़ कर सीधे कलेक्शन वाहनों में डाल देता है। जी-स्पाइडर रोबोट उच्च जलस्तर और लगातार बहाव की स्थिति में भी काम करने में सक्षम है। यह प्लास्टिक, धारदार वस्तुओं और अन्य हानिकारक कचरे को सुरक्षित तरीके से निकाल कर नहरों की सफाई सुनिश्चित करता है। नियमित और व्यवस्थित सफाई से यह शहरी जल निकासी को भी मजबूत करेगा और बाढ़ जैसी समस्याओं को रोकने में मदद करेगा। अधिकारियों ने इसे शहरी स्वच्छता में तकनीक आधारित क्रांतिकारी कदम बताया है, जो न केवल कार्यकुशलता बढ़ाता है बल्कि सफाईकर्मियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। यह मॉडल राज्य के अन्य जोखिमपूर्ण नहरों और ड्रेनेज नेटवर्क में भी अपनाया जा सकता है।

# रांची में गैलेक्सिया मॉल स्थित पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी

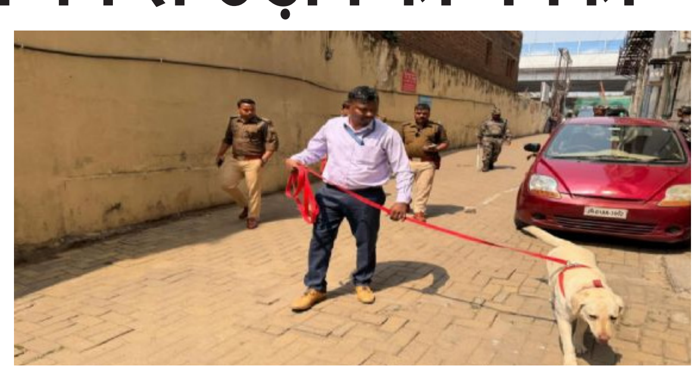

**संवाददाता**

**रांची।** झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस बार ग्लैक्सिया मॉल में स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी के अनुसार, अज्ञात अपराधियों ने ईमेल के माध्यम से धमकी भरा संदेश भेजा, जिसमें रातू रोड स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की बात कही गई।

धमकी भरा मेल मिलने के बाद पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई। कोतवाली पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी। पुलिस और बीडीएस टीम ने पासपोर्ट कार्यालय के अंदर और आसपास के पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली। मॉल परिसर के अलग-अलग हिस्सों में भी सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई। हालांकि, कई घंटों तक चली जांच के दौरान कहीं से भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच जारी रखी गई है। पुलिस अब उस ईमेल की तकनीकी जांच कर रही है, जिसके जरिए धमकी दी गई थी। साइबर टीम की मदद से मेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि पूरे परिसर की जांच की गई है और मामले की तकनीकी जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी रांची में इसी तरह की धमकी का मामला सामने आ चुका है।

कुछ समय पहले रांची सिविल न्यायालय और समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस समय भी अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के जरिए आरडीएक्स से विस्फोट करने की बात कही थी। हालांकि, उस मामले में भी व्यापक तलाशी अभियान के बावजूद कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई थी।

# भारत ने कनाडा से यूरेनियम सप्लाई पक्की की, परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मदद

**संवाददाता**

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कनाडा के साथ 2.6 अरब डॉलर के दीर्घकालिक यूरेनियम सप्लाई समझौते को भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता भारत के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को मजबूत करेगा, जिसके तहत देश 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना चाहता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में घरेलू स्तर पर यूरेनियम उत्पादन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे में लंबे समय के लिए यूरेनियम आयात की व्यवस्था करना जरूरी हो जाता है। रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि भारत में यूरेनियम का घरेलू उत्पादन कुल मांग से काफी कम रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि मौजूदा और भविष्य के परमाणु रिएक्टरों को चलाने के लिए भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसी कारण कनाडा के साथ दीर्घकालिक सप्लाई समझौता रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक कजाकिस्तान से भारत पिछले कुछ वर्षों से यूरेनियम का प्रमुख आयात करता रहा है। अब कनाडा के साथ हुआ यह समझौता भारत के लिए इस अहम ईंधन का एक और बड़ा स्रोत खोल देगा, जिससे देश के परमाणु रिएक्टरों को ऊर्जा मिल सकेगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिसंबर 2025 में भारत की संसद ने नागरिक परमाणु ऊर्जा ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत पहली बार घरेलू और विदेशी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने, उनके मालिक बनने और संचालन करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले यह क्षेत्र पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था। इस सुधार के जरिए लंबे समय से चली आ रही सप्लायर लायबिलिटी से जुड़ी चिंताओं को भी दूर किया गया है और नियामकीय ढांचा अधिक स्पष्ट और स्थिर बनाया गया है।

**एल.आई.सी**
भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।
-भारत सिंह
मो. 9967255741



**महत्वपूर्ण सूचना**

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जाँचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाए या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।


# बादशाह के रैप 'टटीरी' पर महिला आयोग ने जारी किया समन

**संवाददाता**

**चंडीगढ़।** बॉलीवुड रैपर बादशाह हरियाणवी फोक सॉन्ग 'टटीरी' के रीमिक्स रैप पर विवाद में फंस गए हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने गाने के बोल और वीडियो पर आपत्ति के बाद उन्हें समन जारी किया है। बादशाह को 13 मार्च को आयोग के समक्ष पेश होकर पक्ष रखने को कहा गया है।हरियाणा के पानीपत की नारी तू नारायणी संस्था की अध्यक्ष सविता आर्य और शिव आरती फाउंडेशन के प्रमुख शिव कुमार की शिकायत पर महिला आयोग ने यह नोटिस जारी किया है। इसके अलावा रोहतक के एडवोकेट राजनारायण पंघाल ने भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत भेजी है।शिकायत में बादशाह के रैप की लाइन 'आया बादशाह डोली चढ़ाने, इन सबकी घोड़ी बनाने' पर आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि इस गाने में गंदी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही स्कूल ड्रेस में नाबालिग बच्चियों को स्कूल बैग फेंकते हुए दिखाया गया। बादशाह के गीत में छोटी-छोटी नाबालिग बच्चियां हरियाणा के सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और उन्हें अपनी किताबें व बस्ते फेंकते हुए और पढ़ाई से दूर भागते हुए दिखाया गया है।

**मेष:** नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है। परिवार की समस्याओं की चिंता रहेगी। समय की अनुकूलता का लाभ अधिकाधिक लेना चाहिए। नवीन उपलब्धियों की प्राप्ति संभव है। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा।

**वृषभ:** संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी। धन की आवक बनी रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य न करें। लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। शुभ कार्यों में संलग्न होने से सुयश एवं सम्मान प्राप्त हो सकेगा। व्यापारिक निर्णय लेने में देर नहीं करें।

**मिथुन:** रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। आपके व्यवहार एवं कार्यकुशलता से अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। संतान के कार्यों पर नजर रखें। पूंजी निवेश बढ़ेगा। प्रचार-प्रसार से दूर रहें।

**कर्क:** क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दुःखद समाचार मिल सकता है। चिंता बनी रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में सावधानी रखें। वास्तविकता को महत्व दें। प्रयासों में सफलता के योग कम हैं। परिवार में कलह-कलेश का माहौल रह सकता है।

**सिंह:** नए अनुबंधों का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। पूछ-परख रहेगी। रुके कार्य बनेंगे। जोखिम न लें। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यवहार कुशलता एवं सहनशीलता के बल पर आने वाली बाधाओं का समाधान हो सकेगा। खानपान पर नियंत्रण रखें।

**कन्या:** मेहमानों का आवागमन होगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। मान बढ़ेगा। जल्दबाजी न करें। जोखिम के कार्यों से दूर रहें। पराक्रम में वृद्धि होगी। परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा। अभिष्ट कार्य की सिद्धि के योग हैं। उलझनों से मुक्ति मिलेगी।

**तुला:** यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे। भेंट आदि की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में उन्नति के योग हैं। संतान की ओर से सुखद स्थिति बनेगी। प्रयास की मात्रा के अनुसार लाभ की अधिकता रहेगी। अपनी वस्तुएँ संभालकर रखें।

**वृश्चिक:** वाणी पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित बड़े खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है, जोखिम न लें। अजनबी व्यक्ति पर विश्वास न करें। सेहत को लेकर सचेत रहें। उदर विकार के योग बनेंगे। खान-पान पर संयम रखें। विवादों से दूर रहना चाहिए। आर्थिक प्रगति में रुकावट आ सकती है।

**धनु:** कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी। धनार्जन होगा। प्रमाद न करें। संतान के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नेतृत्व गुण की प्रधानता के कारण प्रशासन व नेतृत्व संबंधी कार्य सफल होंगे। शत्रुओं से सावधान रहें।

**मकर:** मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु शांत रहेंगे। धनार्जन होगा। आज विशेष लाभ होने की संभावना है। बुद्धि एवं मनोबल से सुख-संपन्नता बढ़ेगी। व्यापार में कार्य का विस्तार होगा। सगे-संबंधी मिलेंगे।

**कुंभ:** प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। धनार्जन होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, अपना ध्यान रखें। प्रमाद न करें। व्यापार-व्यवसाय में इच्छित लाभ की संभावना है। भाइयों की मदद मिलेगी। संपत्ति के लेनदेन में सावधानी रखें।

**मीन:** वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। दूसरों की जमानत न लें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। व्यापार में नई योजनाओं से लाभ के योग हैं। स्थायी संपत्ति क्रय करने के योग बनेंगे। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भेंट होगी।

# दृष्टिकोण: नफरत फैलाने पर मिले कठोर दंड

**डॉ. सुधाकर आशावादी**

समाज में एक ऐसा वर्ग सक्रिय हो चुका है, जिसे देश में शांति और सुशासन से कोई सरोकार नहीं है, जिसका कार्य ही देश में वैमनस्य को बढ़ावा देना है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसे तत्व भारत की लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब से सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपना चेहरा चमकाने का चलन बढ़ा है, तब से वैमनस्यता बढ़ाने वाले कथ्यों की बाढ़ सी आ गई है। बिना किसी तर्क के इतिहास को अपने मनमुताबिक प्रस्तुत करके समाज में द्वेष, नफरत और घृणा का वातावरण बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। कभी बुराई की प्रतीक होलिका को जाति विशेष का घोषित करके इसे जातीय अपमान की संज्ञा देकर होली के बहिष्कार की बात की जाती है। कभी अपने मतानुसार धार्मिक ग्रंथों में कमियां ढूंढी जाती हैं। मानसिक संकीर्णता के नए नए उदाहरण समाज में समय समय पर प्रस्तुत करके लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाता है। वस्तुस्थिति यह है, कि सोशल मीडिया पर प्रस्तुत सामग्री को तर्क की कसौटी पर नहीं परखा जाता। कभी भारतीय पौराणिक ग्रंथों को कपोल कल्पित बताकर झूठा कहा जाता है, तो कभी उन्हीं ग्रंथों की विषयवस्तु के आधार पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर समाज में किसी ख़ास वर्ग के उत्पीड़न को प्रचारित किया जाता है। आश्चर्य तो तब होता है, कि जब भरे पेट लोग जीवन अनिवार्य प्राकृतिक संसाधनों से स्वयं को वंचित बताकर यह कहते हैं, कि उन्हें आवश्यक प्राकृतिक सुविधाओं से वंचित रखा गया, उन्हें पीने के लिए जल नहीं मिला, रहने के लिए आवास नहीं मिला, सूर्य ने उनके लिए धूप उपलब्ध नहीं कराई। विश्व के किसी कोने में ऐसा कुतर्क सुनाई नहीं देता, जैसा अपने देश में फैलाया जाता है। बहरहाल सामाजिक समरसता बनाए रखने की दिशा में ऐसे विमर्श बाधक हैं। समाज कल्याण तथा देश को एकसूत्र में बांधने की परिकल्पना ऐसे विमर्श से अधूरी ही रहती है। ऐसे में परम आवश्यक है, कि किसी भी माध्यम से समाज को बांटने वाले कथ्य का विस्तार करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का विधान हो। जातीय क्षत्रपों व धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले किसी भी कथ्य को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में भी दोहरा आचरण अपनाने वाले तत्वों पर क़ानूनी अंकुश लगे, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जियो और जीने दो का दायित्व निभाना अनिवार्य होता है। मौलिक दायित्व और अधिकार की पूर्ति में नफरत फैलाने की आजादी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए।

# पालकमंत्री प्रताप सरनाईक ने धाराशिव में 500 बेड के जिला अस्पताल निर्माण को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश

संवाददाता

**मुंबई।** महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में निर्माणाधीन 500 बेड वाले आधुनिक जिला अस्पताल का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश राज्य के परिवहन मंत्री तथा धाराशिव के पालकमंत्री प्रताप सरनाईक और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने दिए हैं। शुक्रवार को मंत्रालय में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक में दोनों मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस जनहितकारी परियोजना को तय समय सीमा में

और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। बैठक में पालकमंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि अस्पताल का निर्माण मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही आने वाले दिनों में इस अस्पताल को आम जनता के लिए शुरू करने की योजना भी बनाई जाए। राज्य सरकार ने धाराशिव जिले के नागरिकों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करीब 360 करोड़ रुपये की लागत से 500 बेड का अत्याधुनिक जिला अस्पताल बनाने को मंजूरी दी है। समीक्षा बैठक में अस्पताल निर्माण के लिए आवश्यक निधि, तकनीकी अड़चनें और काम की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रस्तावित अस्पताल की मुख्य इमारत तीन मंजिला होगी और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 45 हजार वर्गमीटर होगा।

परियोजना के अंतर्गत कैंटीन, धर्मशाला, लॉन्ड्री, मॉर्च्युरी, फार्मेसी भवन, पार्किंग व्यवस्था, गैस मैनिफोल्ड रूम, ऑक्सीजन प्लांट तथा बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन की अलग सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था भी की जाएगी। मंत्रियों ने निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में आंतरिक सड़कें, जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था, अग्निशमन प्रणाली, सौर ऊर्जा प्रणाली, वर्षा जल संचयन, पार्किंग और हरित क्षेत्र विकास जैसे कार्य भी उच्च गुणवत्ता के साथ किए जाएं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना धाराशिव जिले के आम नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस अस्पताल के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य है। बैठक में यह भी बताया गया कि छत्रपति संभाजीनगर में 400 बेड का जिला अस्पताल पहले ही बनाया जा चुका है और जरूरत पड़ने पर वहां का दौरा कर धाराशिव परियोजना में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। बैठक में लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

# अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मीरा-भायंदर में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त

संवाददाता

**मुंबई।** अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को मीरा-भायंदर महानगरपालिका की बस सेवाओं में महिलाओं को पूरे दिन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा महानगरपालिका परिवहन उपक्रम की सभी बसों में लागू रहेगी, जो शहर के भीतर तथा ठाणे और बोरीवली मार्गों पर संचालित होती हैं। मीरा-भायंदर महानगरपालिका की महापौर डिंपल विनोद मेहता ने महिलाओं के सम्मान में यह विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुक्त को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था। इसके बाद महानगरपालिका आयुक्त राधाबिनोद ए. शर्मा ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

महापौर की पहल पर यह सुविधा महिला यात्रियों के सम्मान में लागू की जा रही है। महानगरपालिका परिवहन उपक्रम पिछले पांच वर्षों से महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करता आ रहा है। इस पहल को शहर की महिलाओं से हर वर्ष अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं इसका लाभ उठाती हैं। महानगरपालिका के आंकड़ों के अनुसार 8 मार्च 2021 को 11,552, वर्ष 2022 में 21,461, वर्ष 2023 में 25,838, वर्ष 2024 में 22,131 तथा 8 मार्च 2025 को 33,432 महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा का लाभ लिया था। हर वर्ष बढ़ती संख्या से इस पहल के प्रति महिलाओं में सकारात्मक भावना दिखाई दे रही है। महानगरपालिका के अनुसार इस उपक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना तथा समाज में महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण का संदेश देना है। महापौर डिंपल मेहता, उपमहापौर ध्रुवकिशोर मन्साराम पाटील, स्थायी समिति सभापति हसमुख गेहलोत और महानगरपालिका प्रशासन की ओर से शहर की सभी महिलाओं से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।

# जून 2026 तक प्रोफेसर भर्ती प्रोसेस पूरा हो जाएगा: मंत्री चंद्रकांत पाटिल

संवाददाता

**मुंबई।** सरकार ने राज्य की यूनिवर्सिटी और उनसे जुड़े कॉलेजों में प्रोफेसर के पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। हायर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल ने निर्देश दिया है कि यह भर्ती प्रोसेस तय समय में पूरा किया जाए। ये निर्देश गुरुवार को मुंबई में मौजूद होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई नॉन-एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस-चांसलर की रिव्यू मीटिंग में दिए गए। मीटिंग में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को असरदार तरीके से लागू करने पर भी डिटेल में चर्चा हुई। मंत्री पाटिल ने कहा कि राज्य की यूनिवर्सिटी की नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग सुधारने के लिए नई पनिशमेंट पॉलिसी को असरदार तरीके से लागू करना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी को एकेडमिक क्वालिटी, रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ावा देने, एजुकेशन में इनोवेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस पर खास ध्यान देना होगा। मीटिंग में प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रोसेस पर डिटेल में चर्चा हुई। यूनिवर्सिटी और उनसे जुड़े कॉलेजों में खाली पोस्ट की जानकारी इकट्ठा करने और नियमों के मुताबिक भर्ती प्रोसेस शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी साफ किया गया कि यह पूरा प्रोसेस हर हाल में जून 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। मंत्री पाटिल

ने चेतावनी दी कि अगर तय समय में भर्ती प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो संबंधित यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पोस्ट की संख्या कम करने का एक्शन भी लिया जा सकता है। हायर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बी. डॉ. वेणुगोपाल रेड्डी, हायर एजुकेशन डायरेक्टर। डॉ. शैलेंद्र देवलंकर, टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर। डॉ. विनोद मोहितकर, डायरेक्टर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। प्रमोद नाइक समेत अलग-अलग यूनिवर्सिटी के चांसलर, प्रो-चांसलर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

# सफाले के पारगांव में फार्मेसी कॉलेज के छात्रों का सात दिवसीय सामाजिक सेवा शिविर

संवाददाता

**मुंबई।** एसवीकेएम के डॉ. भानुबेन नानावटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) यूनिट एसबी-34 के विद्यार्थियों ने 22 से 28 फरवरी 2026 के दौरान पारगांव में सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजित कर विभिन्न समाजोपयोगी गतिविधियां संचालित कीं। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों में स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

शिविर के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई पालघर के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस दौरान लोगों को रोगों की रोकथाम और समय पर पहचान के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने "हृदय स्वास्थ्य" विषय पर मराठी में पथनाट्य प्रस्तुत कर हृदय रोगों के कारण, लक्षण, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, तनाव, गलत खानपान और नियमित व्यायाम के महत्व के बारे में प्रभावी संदेश दिया। इस

पथनाट्य को ग्रामीणों से उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला और हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली। इसके अलावा छात्रों ने क्षयरोग (टीबी) के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली, जिसमें टीबी के लक्षण, रोकथाम और उपचार से संबंधित जानकारी दी गई।

ग्राम पंचायत के सहयोग से प्लास्टिक सफाई अभियान भी चलाया गया। इस शिविर के सफल आयोजन में पारगांव (सफाले) के सरपंच अंकुश शांताराम जबर, ग्राम विकास अधिकारी जैनाली भोईर, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रेरणा वाघमारे, डॉ. सौरभ काटवले, प्राध्यापक एंजल गोडाड, अक्षता पहलकर, प्रयोगशाला कर्मचारी विशाल तथा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. मुनिराम मोमीन का विशेष सहयोग रहा। आयोजकों के अनुसार इस शिविर के माध्यम से ग्रामीणों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक जागरूकता बढ़ी है तथा युवाओं की समाज विकास में सक्रिय भागीदारी भी सामने आई है।

# खाद्य रंगों के खतरों पर विधानसभा में चर्चा, सरकार बनाएगी नीति: एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाळ

संवाददाता

**मुंबई।** बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जा रहे विभिन्न रंगों में मौजूद हानिकारक तत्वों के मुद्दे पर राज्य सरकार गंभीर हो गई है। इस विषय पर चर्चा कर खाद्य रंगों को लेकर राज्य की नीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में विधानसभा के इस विषय के जानकार सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के कानूनों में आवश्यक बदलाव के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाएगा। गुरुवार को यह जानकारी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ ने विधानसभा में दी। विधानसभा में सदस्य महेश शिंदे ने खाद्य पदार्थों में रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किए जा रहे हानिकारक कृत्रिम रंगों के उपयोग का मुद्दा उठाते हुए आधे घंटे की चर्चा कराई। इस चर्चा में सदस्य विक्रम पाचपुते, सुधीर मुनगंटीवार, प्रवीण दटके,

राजेश पवार और हिरामन खोसकर ने भी भाग लिया।

मंत्री नरहरी झिरवाळ ने बताया कि अन्न व औषध प्रशासन विभाग से संबंधित कानून केंद्र सरकार के अधीन हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जा रहे हानिकारक रंगों और उनके घटकों पर नियंत्रण के लिए कानूनों में आवश्यक बदलाव करने हेतु राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में खाद्य रंगों के संबंध में राज्य की नीति तय करने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी होटलों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने मेन्यू में खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाले सभी घटकों का स्पष्ट उल्लेख करें। इस निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री झिरवाळ ने बताया कि वर्तमान में राज्य में अन्न व औषध प्रशासन विभाग की तीन प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा तीन नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने सदस्य महेश शिंदे से इस विषय पर प्रस्तुत अध्ययन आधारित जानकारी को पुस्तिका के रूप में तैयार करने का सुझाव दिया और कहा कि विभाग इस कार्य में सहयोग करेगा। साथ ही विभिन्न माध्यमों से जनजागृति अभियान भी चलाया जाएगा।

# महाराष्ट्र में अग्निवीरों के पुनर्वास की तैयारी

संवाददाता

**मुंबई।** महाराष्ट्र में अग्निवीर योजना के तहत देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उन युवाओं की चिंता को दूर करने का बीड़ा उठाया है जो चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अपने भविष्य और रोजगार को लेकर आशंकित थे। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय सेना की 'अग्निवीर' योजना के तहत सेवा दे रहे युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरा फैसला लिया है।

प्रदेश के युवाओं में 4 साल की सेवा के बाद रोजगार को लेकर व्याप्त अनिश्चितता को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने उनके पुनर्वास की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के मंत्री शंभूराज देसाई ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र से अब तक लगभग 11,000 युवाओं का चयन केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के तहत हुआ है। नियमों के अनुसार, इनमें से 25 प्रतिशत (करीब 2,750

युवा) को तो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में स्थायी तौर पर समाहित कर लिया जाएगा। लेकिन, शेष 75 प्रतिशत युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने उठाई है। मंत्री देसाई के अनुसार, सेना से रिटायर होकर आने वाले युवाओं के कौशल का उपयोग राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में किया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का एक विशेष अध्ययन समूह बनाया गया है। यह समूह अपनी रिपोर्ट अगले महीने पेश करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर अग्निवीरों को निम्नलिखित विभागों में प्राथमिकता मिल सकती है। महाराष्ट्र होमगार्ड, वन विभाग सुरक्षा दल, राज्य सुरक्षा कॉर्पोरेशन, पुलिस बल और अन्य वर्दीधारी सेवाएं। अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र और राज्य सरकारों को घेरता रहा है। मुख्य चिंता यह रही है कि 22-23 साल की उम्र में सेवामुक्त होने के बाद ये युवा क्या करेंगे? महाराष्ट्र सरकार का यह कदम न केवल युवाओं का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि विपक्ष के आरोपों पर भी विराम लगाएगा। देसाई ने स्पष्ट किया कि अध्ययन समूह की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विभागों के मंत्रियों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री की अंतिम मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन या अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है।

# नवी मुंबई में अवैध निर्माण ध्वस्त, सिडको ने चलाया बुलडोजर

संवाददाता

**नवी मुंबई।** नवी मुंबई में अवैध निर्माण के खिलाफ सिडको ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 वर्ग मीटर जमीन से कब्जा हटाया। गुरुवार 5 मार्च को लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र के जांभुल पाड़ा इलाके में यह कार्रवाई की गई। यहां सर्वे नंबर 25, 35 और 36 पर लैंड माफियाओं ने सिडको की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर लिया था। सिडको के अवैध निर्माण निरोधक विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से सभी अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण सिडको द्वारा अधिग्रहित जमीन

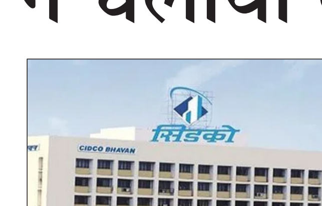


पर बिना किसी अनुमति के किया गया था। कार्रवाई के बाद सिडको ने पूरे भूखंड को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक कब्जा करने वालों ने इस जमीन पर लोहे के पतरे से फेंसिंग कर रखी थी। इसके अलावा वहां एक बड़ा शेड और दो सिक्योरिटी केबिन भी बनाए गए थे। यह अवैध कब्जा सिडको द्वारा प्रस्तावित विकास परियोजनाओं में बाधा बन रहा था, जिसके कारण विभाग ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरी कार्रवाई सिडको के सतर्कता विभाग के मुख्य अधिकारी सुरेश मेगड़े के निर्देश पर की गई। वहीं सिडको के अवैध निर्माण निरोधक विभाग के मुख्य नियंत्रक विशाल धागे के मार्गदर्शन में टीम ने अभियान को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। स्थानीय पुलिस, सिडको से संबद्ध पुलिस टीम, महाराष्ट्र सुरक्षा बोर्ड के सुरक्षा रक्षक और सिडको के सिक्योरिटी गार्ड बड़ी संख्या में तैनात थे। सिडको की इस सख्त कार्रवाई के बाद इलाके में सक्रिय लैंड माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

# YANG'S FRILL-LIMBED TREE FROG RECORDED IN MEGHALAYA FOR THE FIRST TIME

**SHILLONG:** In a notable boost to Meghalaya's biodiversity records, researchers have documented the presence of the Yang's frill-limbed tree frog (Kurixalus yangi) in the state for the first time, indicating that the region's amphibian diversity remains largely unexplored.

According to the official sources the species was discovered during an amphibian survey in Mawpat village of South West Khasi Hills district by Holiness Warjri and Madhurima Das of Assam Don Bosco University, along with wildlife researcher Jayaditya Purkayastha of Help Earth. The tiny frog was recorded on October 10, 2024, at an elevation of around 1,355 metres above sea level. Researchers confirmed the species through detailed morphological examination and genetic analysis of the mitochondrial 16S rRNA gene. The specimen has since been preserved in the zoological collection of Assam Don Bosco University for further scientific study. Originally described from Yunnan in China, Kurixalus yangi has earlier been reported from Myanmar and parts of Northeast India such as Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland. The latest finding extends the species' known distribution to Meghalaya. Scientists say the discovery also highlights growing conservation concerns for amphibians in the state. Climate change, habitat loss and the harvesting of frogs for food are considered major threats to amphibian populations. Researchers emphasised that continued surveys and conservation efforts will be vital to better understand and protect Meghalaya's fragile amphibian habitats while uncovering more hidden species in the region.

# YOGI ARRIVES TO ATTEND COORDINATION MEET OF RSS VICHAR PARIVAR

**KANPUR:** Chief Minister Yogi Adityanath arrived in Kanpur on Friday to attend a coordination meeting of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)'s Vichar Parivar. His helicopter landed at the helipad on the Chandrashekhar Azad University of Agriculture and Technology campus, where he was welcomed by BJP representatives and officials. In this meeting, held at Pandit Deendayal Upadhyay Sanatan Dharma Vidyalaya in Nawabganj, Chief Minister Yogi Adityanath will spend approximately two and a half hours brainstorming with officials from various organizations. Ex-BJP State President Bhupendra Singh Chaudhary and State Organization General Secretary Dharampal Singh, along with several prominent officials associated with the Vichar Parivar, will also be present. The meeting will discuss organizational strategy, public relations campaigns, and other political issues related to the upcoming assembly elections in 2027. Discussions will also be held on strengthening coordination between the Sangh and the BJP. Following the meeting, Chief Minister Yogi Adityanath will also visit the residence of BJP MLA Mahesh Trivedi in Kidwai Nagar. There, he will attend a ceremony celebrating the MLA's daughter's recent wedding and bless the newlyweds.

# Iran war disrupts airline service, eight flights cancelled, over 450 people cancel tickets

**LUCKNOW:** Flight operations to Gulf countries have been disrupted since the attack on Iran. A series of flight cancellations continues. Flight operations between Amausi Airport and Gulf countries have not yet returned to normal. On Thursday, eight flights to Dammam, Dubai, and Abu Dhabi were canceled, resulting in the cancellation of over 450 tickets. Airlines issued refunds totaling Rs. 2.25 lakh (approximately $250,000 USD). Several airlines have stated they will reissue tickets once the situation returns to normal.

Flight operations to Gulf countries have been disrupted since the attack on Iran. Due to the closure of Iran and Dubai's airspace, flights from Lucknow to Gulf countries have been canceled. The number of flights, which was 17 previously, dropped to eight on Thursday. Air India Express flight IX-193 to Dubai, Indigo flight 6E-1415 to Abu Dhabi, and Indigo flight 6E-097 to Dammam were canceled. IndiGo flight 6E-1424 from Sharjah to Lucknow, Air India Express flight IX-198 from Dubai, IndiGo flight 6E-1416 from Abu Dhabi, IndiGo flight 6E-098 from Dammam, and Air India Express flight IX-194 from Dubai were all canceled. Meanwhile, at Amausi Airport, passengers and their families thronged the counters to get flight information.

Passengers are also worried about refunds: Dhirendra Singh booked a flight from Dubai to Lucknow. He has been worried about a refund since his flight was canceled on March 3rd. Similarly, Mohammad Ikhlaq Ahmed booked a ticket to Riyadh. His ticket was canceled due to the airspace closure, but he has not received a refund yet. Contacting the airline said the money had been transferred to the ticket agent's account. Date prices surge, war creates uncertainty over imports: With the increase in demand for dates, the prices have also increased. Due to the ongoing tensions between Iran and Israel, there is uncertainty regarding date imports from Gulf countries. Traders say the increase in wholesale prices is limited, but the impact is more pronounced in the retail market, forcing customers to pay higher prices. Wholesale traders currently report adequate stock of dates, but retailers in major markets, including Chowk, Aminabad, and Nakkhas, have slightly increased prices in anticipation of a potential import crisis. Rashid, a date trader in Chowk, explained that demand is higher than ever due to Ramadan. While the market currently has stock, new supplies have not arrived. If the situation in West Asia remains the same for a long time, prices could rise further. Wholesaler Danish said that the price of dates in the wholesale market is roughly the same as before, but traders Junaid Khan of Aminabad and Bhure of Dandia say that the wholesale market has seen a rise of five to ten rupees per kilogram in the last seven days.

# तामिळनाडूमध्ये १७ जुलैपासून डिजिटल जनगणना होणार सुरू

**चेन्नई:** तामिळनाडू सरकारने राज्यात जनगणना करण्यासाठी अधिकृत आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, तामिळनाडूमध्ये १७ जुलै रोजी जनगणना सुरू होईल. पहिला टप्पा ३० ऑगस्टपर्यंत चालेल, एकूण ४५ दिवस. यावेळी, जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाईल, ज्यामध्ये सर्व डेटा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रेकॉर्ड केला जाईल. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या कामासाठी अंदाजे ५० हजार सरकारी कर्मचारी तैनात केले जातील. हे कर्मचारी घरोघरी जाऊन लोकांशी संपर्क साधतील आणि त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीबद्दल माहिती गोळा करतील. कर्मचारी एकूण ३३ प्रश्न विचारतील, ज्यांची उत्तरे डिजिटल पद्धतीने रेकॉर्ड केली जातील. जनगणनेदरम्यान, कर्मचारी घरांची परिस्थिती, मालमत्ता, वाहने आणि मूलभूत सुविधांबद्दल माहिती गोळा करतील. यामध्ये घर भाड्याने घेतले आहे की मालकीचे आहे, कुटुंबाचे उत्पन्न, घरात शौचालय आहे का आणि घरात सायकल, दुचाकी किंवा कार आहे का यासारख्या प्रश्नांचा समावेश आहे. रेफ्रिजरेटर आणि एअर कंडिशनरसारख्या सुविधांच्या उपलब्धतेबद्दल देखील प्रश्न विचारले जातील. जनगणनेच्या कामात गुंतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मानधन (भत्ता) आणि इतर आवश्यक तरतुदींचा समावेश करून तामिळनाडू सरकारने हा सरकारी आदेश जारी केला आहे, जेणेकरून हे काम सुरळीतपणे पूर्ण करता येईल. दरम्यान, केंद्र सरकारने २०२७ ची राष्ट्रीय जनगणना दोन टप्प्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिला टप्पा राज्यांमध्ये वेळापत्रकानुसार केला जाईल, तर दुसरा टप्पा पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. या देशव्यापी जनगणनेत सुमारे ३२ लाख सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी होतील.

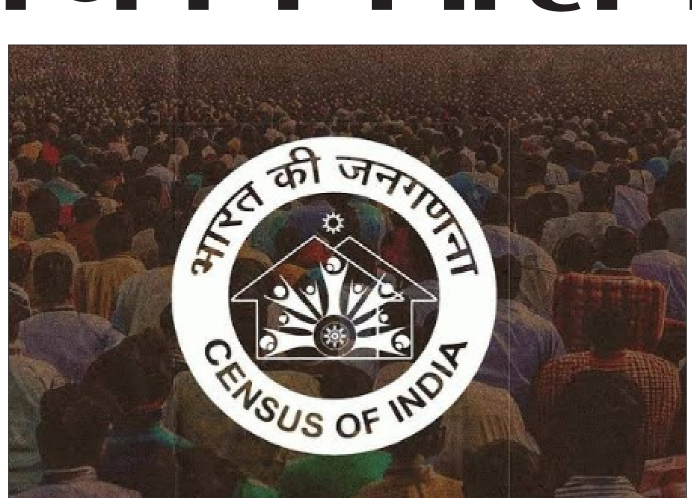


देशातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी जनगणना अत्यंत महत्त्वाची आहे असे सरकारचे मत आहे. जनगणनेतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, केंद्र सरकार लोकांच्या जीवनात आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यास मदत करणाऱ्या नवीन योजना विकसित आणि अंमलात आणते. म्हणून, जेव्हा जेव्हा जनगणनेशी संबंधित सरकारी कर्मचारी तुमच्या घरी येतात तेव्हा तुम्ही त्यांना अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे. जर त्या वेळी घरातील सदस्य उपस्थित नसतील तर काळजी करण्याची गरज नाही, कारण कर्मचारी नंतर पुन्हा येऊ शकतात.

# छत्तीसगडच्या जशपूर जिल्ह्यात बस उलटल्याने 6 जणांचा मृत्यू, 9 गंभीर

**रायपूर:** छत्तीसगडमधील जशपूर जिल्ह्यातील करडेगाहून कुनकुरीकडे जाणारी एक प्रवासी बसचे अचानक नियंत्रण सुटले आणि उलटली. या अपघातात एका मुलासह सहा प्रवाशांचा मृत्यू झाला तर नऊ जण गंभीर जखमी झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, करडेगाहून कुनकुरीकडे जाणारी एक प्रवासी बस दोन डझनहून अधिक प्रवाशांना घेऊन जात होती. करडेगा चौकी परिसरातील गोडा अंबाजवळ बस नियंत्रणाबाहेर गेली आणि उलटली. या अपघातामुळे लोकांमध्ये संताप व्यक्त होत होता. स्थानिकांनी बचावकार्य सुरू केले आणि पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच प्रशासनाने घटनास्थळी रुग्णवाहिका पाठवत घटनास्थळी धाव घेतली. सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक प्रवासी जखमी झाले, त्यांना कुनकुरी सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या कॅम्प ऑफिसने सर्व जखमींना सर्वोत्तम उपचार मिळावेत यासाठी तात्काळ सूचना जारी केल्या आहेत. पोलीस आणि प्रशासकीय पथके घटनास्थळी उपस्थित आहेत आणि संपूर्ण घटनेचा तपास केला जात आहे. पोलीस मृतांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि अधिक माहितीची वाट पाहत आहेत.

# महावितरणच्या विरोधात सोलर विक्रेत्यांचा सोलापुरात मोर्चा

**सोलापूर:** महावितरणने प्रधानमंत्री सूर्य घर वीज योजनेसाठी लागू केलेल्या नव्या नियमांच्या विरोधात सोलर असोसिएशन ऑफ सोलापूरने गुरुवारी मोर्चा काढून विरोध दर्शविला. चार हुतात्मा पुतळ्यापासून मोर्चाला प्रारंभ झाला. सेवासदन प्रशाला, रामलाल चौक, नवी वेस पोलिस चौकी मार्गे जुनी मिल कंपाऊड येथील महावितरण कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन महाविरणचे अधिक्षक अभियंता सुनील माने यांच्याकडे सुर्पूद केले. प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजने अंतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या सौर प्रकल्पांच्या क्षमतेबाबत महाविरणने नवा नियम लागू केला आहे. 13 फेबुरवारीपासून ग्राहकांच्या मागणीनुसार सोलार प्रकल्पाची क्षमता मंजूर केली जाणार नसून मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी सरासरी वीज वापरावर आधारीतच सोलार प्रकल्पाची क्षमता निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे सोलार विक्रेते आणि उद्योजकांसह ग्राहकांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महावितरणने केंद्र सरकारने जाहीर केलेले योजनेचे नियम मोडीत काढून मागील 12 महिन्याच्या वीज वापरावर आधारित परवानगी देण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा अन्यायकारक असल्याचे सोलर विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.

# कर्नाटकात 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदीचा प्रस्ताव

**बेंगळुरू:** कर्नाटक राज्याचा अर्थसंकल्प (2026-27) सादर करताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज, शुक्रवारी अल्पवयीन मुलांच्या मोबाईल वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठी घोषणा केली. राज्यात 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेल्या सुमारे 4.48 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण उपक्रम आणि ऑनलाइन सुरक्षेसाठी नियामक उपाय यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे

विद्यार्थ्यांना डिजिटल जगात सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी सांगितले की, मुलांमध्ये वाढत असलेल्या मोबाईल वापराच्या नकारात्मक परिणामांना आळा घालण्यासाठी 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर बंद केला जाईल. हा नियम लागू झाल्यास कर्नाटक हे मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल. याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित शिक्षण प्रणाली सुरू करण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. राज्य सरकार यासाठी धारवाड येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिक डिजिटल ट्यूटरिंग प्रणाली सुरू करणार आहे. या या उपक्रमामुळे सुमारे 12.2 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होण्याची अपेक्षा असून हा प्रकल्प सुमारे 5 कोटी रुपयांच्या खर्चात राबविण्यात येणार आहे. तसेच बेंगळुरूमधील विश्वेश्वरय्या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा विकास इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) प्रमाणे करण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी चालू वर्षात 100 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

# कृति सेनन विवाद पर यामी गौतम की सफाई, कहा- गलती से हुआ लाइक

सोशल मीडिया में इन दिनों 'बेस्ट एक्ट्रेस' अवॉर्ड को लेकर बहस तेज हो गई है। अभिनेत्री यामी गौतम और कृति सेनन के प्रशंसकों के बीच यह विवाद छिड़ गया है कि दोनों में से बेहतर अभिनेत्री कौन है। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा विवाद यामी गौतम द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट को 'लाइक' करने के बाद शुरू हुआ। हालांकि, अब यामी गौतम ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि उनका किसी भी अभिनेत्री को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। यामी गौतम ने अपने 'लाइक' को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि एक सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें रोजाना कई पोस्ट में टैग किया जाता है और कई बार यह स्पष्ट नहीं होता कि पोस्ट किसके संदर्भ में है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'मुझे पता चला है कि मैंने एक ऐसी रील को 'लाइक' किया है, जिसे किसी अन्य कलाकार के प्रति अपमानजनक माना जा रहा है। हमें रोजाना कई पोस्ट में टैग किया जाता है और यह भी एक अवॉर्ड समारोह से जुड़ी किसी अन्य टैग की तरह ही दिखाई दिया। ऐसा बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया गया था। संभव है कि यह गलती से क्लिक हो गया हो।' यामी गौतम ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास कोई पीआर टीम नहीं है और उन्हें ऐसे 'घटिया पीआर हथकंडे' अपनाने नहीं आते। दरअसल, जिस पोस्ट को यामी गौतम ने 'लाइक' किया था, उसमें एक तरफ कृति सेनन की तस्वीर और दूसरी तरफ यामी गौतम की तस्वीर लगाई गई थी। पोस्ट में कृति सेनन की तुलना में यामी गौतम को 'बेस्ट एक्ट्रेस' अवॉर्ड के लिए अधिक योग्य बताया गया था। गौरतलब है कि कृति सेनन को फिल्म 'तेरे इश्क में' के लिए 'बेस्ट एक्ट्रेस' का अवॉर्ड मिला था। इसी पोस्ट को लाइक किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और दोनों अभिनेत्रियों के प्रशंसक आपस में भिड़ गए।

हालांकि, अब यामी गौतम ने अपने बयान के जरिए साफ कर दिया है कि यह सब अनजाने में हुआ और उनका किसी तरह का विवाद खड़ा करने का कोई इरादा नहीं था।

# रश्मिका-विजय के जश्न में नीना गुप्ता की एंट्री

सोशल मीडिया पर इस समय पावर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के हैदराबाद में हुए रिसेप्शन की खूबसूरत तस्वीरें छाई हुई हैं, जिसमें साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई दिग्गज एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, और नामी चेहरे ने स्टाइलिंश अंदाज में सिरकत की। बीते बुधवार को रश्मिका और विजय के रिसेप्शन में पहुंचे सेलेब्रिटीज में एक नाम नीना गुप्ता का भी है, जो हिंदी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री की एक शानदार अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता हैं। कपल के रिसेप्शन में अभिनेत्री अपने पति विवेक मिश्रा के साथ पहुंची। अभिनेत्री के बीते दिन की एक खूबसूरत तस्वीर को गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'आप दोनों और आपके परिवारों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सब बहुत ही मिलनसार, सम्मानजनक और प्यारे थे। भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें। नीना और विवेक की ओर से आपको दोनों को ढेर सारा प्यार।'

रश्मिका और विजय के साथ नीना और उनके पति की खूबसूरत तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। पोस्ट पर कुछ ही घंटे में हजारों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। वहीं, नीना के रिसेप्शन लुक की बात करें तो उन्होंने सफेद रंग की एक एलेगेंट सारी पहनी है, जिसपर गोल्डन प्रिंट हैं।

कट स्लीव ब्लाउज में अभिनेत्री का लुक काफी शानदार लग रहा है। खुले बाल, लाइट मेकअप और गोल्डन ज्वैलरी से नीना के लुक की एलेगेंस काफी बढ़ जाती है। इसी के साथ अभिनेत्री ने हाथ में एक लाल रंग का बैग रखा हुआ है। वहीं, उनके पति विजय काले रंग के कोट और ब्राउन पैंट में उनको काफी कंप्लीमेंट कर रहे हैं।

रश्मिका और विजय के रिसेप्शन लुक की बात करें, तो अभिनेत्री ने प्लेन लाल रंग की साड़ी पहनी है, जिसका बॉर्डर भारी है। स्लीक बन, नेचुरल मेकअप, और गोल्डन ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपनी रिसेप्शन लुक को पूरा किया है। वहीं, विजय पूरी तरह साउथ इंडियन लुक में नजर आ रहे हैं।

# बचपन की यादों को याद कर भावुक हुईं सेलिना जेटली

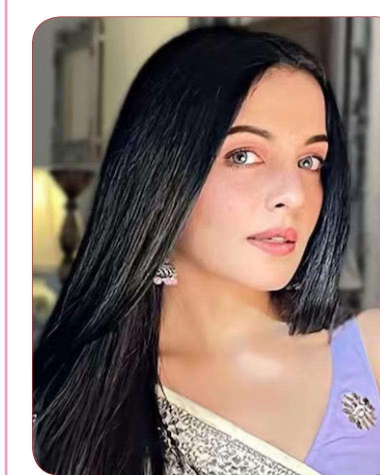

अभिनेत्री सेलिना जेटली ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने जीवन के उतार-चढ़ाव, विदेश प्रवास और अपनी पहचान के संघर्ष पर दिल की बात कही। उन्होंने भारत वापसी की जानकारी देते हुए अपने मन के खालीफन और उदासी को व्यक्त किया। सेलिना ने लिखा कि जब कोई व्यक्ति विदेश में उतना लंबा समय व्यतीत कर लेता है, जितना उसने अपने बचपन में माता-पिता के साथ बिताया हो, तो वह अपनी जड़ों और पहचान को लेकर असमंजस में पड़ जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रिया (आल्प्स) के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना अपने बचपन की यादों, यानी कुमाऊं के पहाड़ों और जंगलों से की। हालांकि, अभिनेत्री ने यह भी साझा किया कि वर्षों विदेश में रहने के बावजूद वहां उन्हें मात्र 'पीटर की भारतीय पत्नी' के रूप में ही पहचाना गया। उन्होंने लिखा, 'पीटर हाग से मेरी शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर ऑस्ट्रिया में बसीं, लेकिन समय के साथ घर जैसा एहसास कम होता गया।'

अभिनेत्री ने अपनी मां की बात को याद करते हुए लिखा, 'आप एक ही इंसान को दो बार नहीं पा सकते, यहां तक कि उसी इंसान को भी नहीं। मां के साथ बिताया समय मेरा सबसे प्रिय समय था। अब जब मां-पिता और परिवार के सदस्य नहीं रहे, तो पुराना घर और एहसास वापस नहीं आता। कभी-कभी लोग ठीक होना भी नहीं चाहते, क्योंकि दर्द ही खोई हुई चीज से आखिरी रिश्ता बन जाता है।'

एक सैनिक की बेटी होने के कारण उनका बचपन कई जगहों पर बीता। कोई एक स्थायी घर नहीं था, लेकिन माता-पिता ने हर जगह प्यार और खुशियां दीं। अभिनेत्री ने लिखा, 'अब विदेशी शादी और परिवार की कमी के कारण मुझे लगता है कि मेरा घर अब कहीं नही है। न ही मैं पूरी भारतीय और न ही विदेशी। मैं दो दुनियाओं का अच्छा हिस्सा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब कोई भी जगह पूरी तरह घर जैसी नहीं लगती।'

सेलिना ने अपने पहाड़ों, जंगलों, बाघों और बचपन की यादों को घर का हिस्सा बताया। वे कहती हैं कि भारत लौटने पर उम्मीद थी कि पुराना अपनापन मिलेगा, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। उन्होंने लिखा, 'अब मैं खुद से पूछती हूं कि मैं सच में कहां की हूं।'

# थकान और शरीर दर्द का कारण हो सकती है विटामिन-D की कमी

**आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थकान, चिड़चिड़ापन और शरीर में दर्द होना आम समस्या बन चुकी है। अक्सर लोग इसे तनाव, नींद की कमी या उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो इसके पीछे एक बड़ी वजह विटामिन-डी की कमी भी हो सकती है, जो धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमजोर बना देती है।**

**क्या है विटामिन-डी और क्यों है जरूरी?**

विटामिन-डी को 'सनशाइन विटामिन' कहा जाता है। यह हड्डियों को मजबूत रखने, इम्युनिटी बढ़ाने और मांसपेशियों की सही कार्यक्षमता के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी शरीर में कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकती है।

**विटामिन-डी की कमी के छिपे लक्षण**

**1. हर समय थकान महसूस होना**

अगर आप पूरी नींद लेने के बाद भी दिनभर सुस्ती और कमजोरी महसूस करते हैं, तो यह विटामिन-डी की कमी का संकेत हो सकता है।

**2. बार-बार मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन**

डिप्रेशन, एंग्जायटी या बिना वजह मूड खराब रहना भी विटामिन-डी लेवल कम होने से जुड़ा माना जाता है।

**3. हड्डियों और जोड़ों में दर्द**

पीठ दर्द, घुटनों में दर्द या शरीर में अकड़न ये सभी संकेत हड्डियों के कमजोर होने की ओर इशारा करते हैं।

**4. बार-बार बीमार पड़ना**

कम इम्युनिटी के कारण सर्दी-जुकाम या इंफेक्शन जल्दी होना भी इसकी कमी का लक्षण हो सकता है।

**5. मांसपेशियों में कमजोरी**

चलते समय संतुलन बिगड़ना या मांसपेशियों में दर्द रहना भी एक अहम संकेत है।

**विटामिन-डी की कमी क्यों होती है?**

- धूप में कम समय बिताना
- सनस्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल
- गलत खान-पान
- बढ़ती उम्र
- लंबे समय तक घर के अंदर रहना

**कैसे पूरी करें विटामिन-डी की कमी?**

- रोज सुबह 20-30 मिनट धूप में रहें
- डाइट में दूध, दही, अंडा, मछली और मशरूम शामिल करें
- डॉक्टर की सलाह से विटामिन-डी सप्लीमेंट लें

**कब करवाएं जांच?**

अगर ऊपर बताए गए लक्षण लंबे समय से बने हुए हैं, तो एक बार Vitamin D Blood Test जरूर करवाएं और डॉक्टर से सलाह लें।

**ध्यान रखें** - समय रहते विटामिन-डी की कमी पहचान लेने से हड्डियों की कमजोरी, डिप्रेशन और इम्युनिटी से जुड़ी कई समस्याओं से बचा जा सकता है।

# ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए जरूरी सावधानियां

ब्रेन स्ट्रोक एडल्ट्स में शारीरिक अक्षमता का एक प्रमुख कारण है। यह तब होता है जब दिमाग तक खून की आपूर्ति बाधित होती है या दिमाग की कोई नस फट जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। समय पर इसके लक्षणों को पहचानना और जोखिम कारकों को कंट्रोल करना ही इससे बचने का एकमात्र प्रभावी रास्ता है।

**ब्रेन स्ट्रोक के प्रमुख लक्षण**

- चेहरे, हाथ या पैरों में अचानक सुन्नपन या कमजोरी।
- बोलने में कठिनाई, शब्दों का लड़खड़ाना या भ्रम की स्थिति।
- देखने में धुंधलापन या शरीर का संतुलन बिगड़ना।
- बिना किसी स्पष्ट कारण के सिर में असहनीय तेज दर्द।

**ऐसे कम करें ब्रेन स्ट्रोक का जोखिम**

- **हाई ब्लड प्रेशर-** यह स्ट्रोक का सबसे बड़ा दुश्मन है। बुजुर्गों में यह खतरा चार गुना तक बढ़ जाता है। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर की सलाह लें।
- **धूम्रपान-** यह दिमाग में ब्लॉकेज के खतरे को दोगुना और हेमरेज के खतरे को चार गुना बढ़ा देता है।
- **हृदय रोग-** अनियमित धड़कन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज ब्लड क्लॉट बनाकर ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकती है। ऐसे में हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप जरूरी है।
- **डायबिटीज-** शुगर लेवल बढ़ने से रक्त धमनियों (Blood Vessels) को नुकसान पहुंचता है, जो स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है।
- कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन शरीर में 'बेड कोलेस्ट्रॉल' (LDL) की अधिकता धमनियों को सिकोड़ देती है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है।
- **एक्टिव न रहना-** मोटापा और व्यायाम की कमी स्ट्रोक के खतरे को तीन गुना बढ़ा सकती है।

# पाचन कमजोर है तो मल्टीग्रेन आटे से रहें सावधान

**आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग मल्टीग्रेन आटे को अपनी डाइट का अहम हिस्सा बना रहे हैं। यह सोचकर कि इसमें कई अनाजों का मिश्रण है, तो यह अधिक पौष्टिक और फायदेमंद होगा। इसमें कोई शक नहीं कि मल्टीग्रेन आटा कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन क्या यह हर किसी के लिए और हर मौसम में फायदेमंद है? एक्सपर्ट्स की मानें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भी हमेशा सिर्फ मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं, तो आपको कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए, क्योंकि यह आपके पेट से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है।**

**मल्टीग्रेन आटा कब हो सकता है नुकसानदेह?**

एक्सपर्ट्स बताती हैं कि अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट फूलना, बदहजमी, या भूख न लगने जैसी शिकायतें रहती हैं, तो आपको मल्टीग्रेन आटा खाने से बचना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसे हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। दरअसल, मल्टीग्रेन आटे में कई तरह के अनाज होते हैं, जिनमें से कुछ भारी हो सकते हैं या जिनकी तासीर अलग-अलग होती है। जब पाचन तंत्र पहले से ही कमजोर हो या उसमें कोई समस्या हो, तो इतने सारे अनाजों को एक साथ पचाना मुश्किल हो जाता है। इससे पेट पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिससे अपच, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को अलग-अलग अनाजों के मिश्रण से एलर्जी या संवेदनशीलता भी हो सकती है, जिससे पाचन संबंधी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं।

**मौसम के मुताबिक सिंगल ग्रेन आटा खाएं:**

हमारे पूर्वज हमेशा मौसम के अनुसार अपने आहार में बदलाव करते थे, और यह बात अनाजों पर भी लागू होती है। मौसम की प्रकृति के अनुसार अनाज का चुनाव करना शरीर को संतुलित रखने और पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है।

- मानसून में रागी या बेसन की रोटी खाएं: यह मौसम नमी वाला होता है और हवा में नमी बढ़ने से पाचन अग्नि मंद हो जाती है। ऐसे में, रागी और बेसन जैसे अनाज हल्के और सूखने वाले होते हैं, जो शरीर की अतिरिक्त नमी को मैनेज करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये आसानी से पच जाते हैं और पेट को हल्का रखते हैं।
- **सर्दी में बाजरा या ज्वार का आटा खाएं:** सर्दी का मौसम ठंडा होता है, और इस दौरान शरीर को आंतरिक गर्मी की आवश्यकता होती है। बाजरा और ज्वार जैसे अनाज गर्म तासीर वाले होते हैं। ये शरीर में आंतरिक गर्मी पैदा करते हैं और चायपचाय (मेटाबॉलिज्म) को सहारा देते हैं। ये अनाज ऊर्जा प्रदान करते हैं और ठंड से लड़ने में मदद करते हैं, साथ ही पाचन को भी मजबूत रखते हैं।
- गर्मी में जौ या चावल का आटा शामिल करें: गर्मी में शरीर को शीतलता की आवश्यकता होती है। जौ और चावल के आटे की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर की गर्मी और एसिडिटी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये अनाज शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं और गर्मी के मौसम में होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं से बचाते हैं।
- मल्टीग्रेन आटा निश्चित रूप से पौष्टिक होता है, लेकिन इसका उपयोग सोच-समझकर करना चाहिए। यदि आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं, तो मौसम के अनुसार सिंगल ग्रेन आटे का सेवन करना आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखेगा, बल्कि आपके शरीर को मौसम के अनुकूल ऊर्जा और पोषण भी प्रदान करेगा। अपने शरीर की सुनें और समझें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। स्वस्थ रहें, संतुलित रहें!

स्वर्णिम प्रदेश



# झांसी में जल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

## पेयजल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

देवेश प्रताप सिंह राठौर

**झांसी, उत्तर प्रदेश।** उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में झांसी, जालौन और ललितपुर जिलों के विभागीय अधिकारियों के साथ आवश्यक समीक्षा बैठक राजघाट कॉलोनी स्थित केन-बेतवा लिंक परियोजना के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था और जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने जल निगम के सभी अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन कम से कम पाँच गांवों का भ्रमण कर पेयजल आपूर्ति की स्थिति का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान गांवों में अधिक से अधिक ग्रामीणों की उपस्थिति में जनचौपाल आयोजित कर लोगों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए नवाचारों के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के

निर्देश दिए गए, ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को पर्याप्त और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। मंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नहरों की सफाई और सुरक्षा से संबंधित नवाचारों के वीडियो एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि नहरों में उगने वाली सिवार किस्म की घास की सफाई के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। झांसी सदर विधानसभा क्षेत्र में नहरों की सफाई के दौरान मंत्री ने सीपरी नहर पर लाइनिंग कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि नहर के पानी का बेहतर उपयोग हो सके। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाकर पहुज नदी की सफाई और संरक्षण का कार्य करने को भी कहा गया, जिससे नदी में जल स्रोत बनाए रखा जा सके। उन्होंने झांसी मंडल के तीनों जिलों में सड़कों पर बने पुराने पुल और पुलियों की मरम्मत योजनाबद्ध तरीके से शीघ्र पूरा कराने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में संचालित पेयजल परियोजनाओं, सिंचाई के लिए बांधों और नहरों में जल भंडारण की स्थिति तथा गर्मी के मौसम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की तैयारियों के बारे में मंत्री को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही शासन के निर्देशों के अनुसार नहरों की सफाई, सुरक्षा और पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया गया। इस समीक्षा बैठक में विधायक रवि शर्मा, विधायक रश्मि आर्य, विधायक जवाहर लाल राजपूत, विधायक राजीव सिंह पारीछा, विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन, विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल तथा अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे योगेंद्र कुमार सहित सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग और जल निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

# वीबी-जी-राम-जी योजना महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना के विपरीत: सिद्धारमैया

संवाददाता

**बेंगलुरु।** कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को समाप्त कर वीबी-जी-राम-जी योजना लागू किए जाने को अधिकार आधारित रोजगार व्यवस्था को कमजोर करने वाला कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना के भी विपरीत है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना के लागू होने से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत मांग आधारित रोजगार गारंटी प्रणाली से हटकर केंद्र ने निर्धारित रोजगार आवंटन प्रणाली लागू होने की आशंका है। इससे ग्रामीण श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के भी विरुद्ध है और इससे पंचायतों के निर्णय लेने के अधिकार पर असर पड़ने की आशंका

है। योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में केंद्रीकरण बढ़ने की संभावना भी उन्होंने जताई। सिद्धारमैया के अनुसार, यदि अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारों की भागीदारी की व्यवस्था की जाती है तो इससे ग्रामीण मजदूरों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्र के प्रशासनिक और नियामक नियंत्रणों के कारण कार्यों के समय पर क्रियान्वयन में भी बाधा आ सकती है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाते हुए ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने वाली पूर्व व्यवस्था को पुनः बहाल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर कानूनी लड़ाई सहित सभी कदम उठाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

# एनएचएआई ने 5100 से अधिक महिलाओं को टोल प्लाजा पर किया तैनात

संवाददाता

**नई दिल्ली।** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे स्थित टोल प्लाजा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देशभर में 1,140 से अधिक टोल प्लाजा पर दिन की शिफ्ट में 5,100 से अधिक महिला कर्मचारियों को तैनात किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य टोल संचालन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और टोल प्लाजा पर यात्रियों को अधिक संवेदनशील और उपयोगकर्ता अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का कहना है कि महिला कर्मचारियों की तैनाती से विवादों की संभावना कम होगी और सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। एनएचएआई ने इस निर्णय पर विभिन्न हितधारकों, टोल ऑपरेटरों और उद्योग संगठनों जैसे नेशनल हाईवेज बिल्डर फेडरेशन, हाईवे ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया यूज़र फी कॉन्ट्रैक्टर्स फेडरेशन से चर्चा की थी। सभी ने

इस पहल का समर्थन किया और महिला कर्मचारियों को दिन की शिफ्ट में तैनात करने पर सहमति जताई। एनएचएआई ने कहा कि महिला कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को। प्रशिक्षण में शिष्ट व्यवहार, आपात स्थिति से निपटने की क्षमता, सुरक्षा प्रोटोकॉल और टोल संचालन की दक्षता पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम न केवल महिलाओं को रोजगार देगा बल्कि उन्हें सामाजिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भागीदारी का अवसर भी प्रदान करेगा। एनएचएआई का मानना है कि इस तरह की पहल से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और टोल प्लाजा पर सेवा वितरण में सुधार होगा।

# पुरानी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट

## उन्नाव के दो गांवों में 8 लोग घायल, पुलिस जांच में जुटी

भूपेन्द्र सिंह

**उन्नाव, उत्तर प्रदेश।** सदर कोजीटीतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों ओर से कुल 8 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। बता दे कि यह घटना अचली खेड़ा और भवानी खेड़ा गांवों के निवासियों के बीच हुई। जानकारी के अनुसार, इन दो परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। किसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिसके बाद कहासुनी मारपीट में बदल गई। दोनों ओर से लाठी-डंडे भी चले। प्रथम पक्ष से भवानी खेड़ा निवासी सुशील, मुन्नू लाल और मनीष घायल हुए। वहीं, द्वितीय पक्ष से ओम प्रकाश (पुत्र छोटा), बिमला, ओम प्रकाश, राम औतार, रीता (पत्नी सुरेश), नीलम और अजय कुमार को चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप

कर विवाद शांत कराया और पुलिस को सूचना दी। सदर कोतवाली पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। सभी घायलों को तत्काल उन्नाव जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण हुआ। चिकित्सकों के अनुसार, अधिकांश घायलों को सामान्य चोटें आई हैं, जबकि कुछ को निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से घटना के संबंध में जानकारी ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

# यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित

संवाददाता

**नई दिल्ली।** संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। आयोग के अनुसार लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी, जबकि साक्षात्कार दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित किए गए।

इन चरणों के आधार पर कुल 958 अभ्यर्थियों को विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। इन अभ्यर्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं के समूह 'ए' और 'बी' में नियुक्ति के लिए चुना गया है। परीक्षा परिणाम के अनुसार शीर्ष दस स्थानों पर चयनित अभ्यर्थियों में अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे

एम और तीसरे स्थान पर अकांश धुल रहे। चौथे स्थान पर राघव झुनझुनवाला, पांचवें स्थान पर ईशान भटनागर, छठे स्थान पर जिन्निया अरोरा, सातवें स्थान पर ए.आर. राजाह मोहाइदीन, आठवें स्थान पर पक्षाल सेक्रेट्री, नौवें स्थान पर आस्था जैन और दसवें स्थान पर उज्ज्वल प्रियांक रहे। आयोग के अनुसार कुल चयनित 958 उम्मीदवारों में सामान्य वर्ग के 317, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 104, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 306, अनुसूचित जाति (एससी) के 158 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 73 अभ्यर्थी शामिल हैं।

# तमिलनाडु में 17 जुलाई से शुरू होगी डिजिटल जनगणना

संवाददाता

**चेन्नई।** तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जनगणना कराने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार तमिलनाडु में जनगणना का कार्य 17 जुलाई से शुरू होगा। इसका पहला चरण 30 अगस्त तक चलेगा, जो कुल 45 दिनों का होगा। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल पद्धति से की जाएगी, जिसमें सभी आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज किए जाएंगे।

राज्य सरकार के अनुसार, इस कार्य में लगभग 50 हजार सरकारी कर्मचारी लगाए जाएंगे। ये कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। कर्मचारियों द्वारा लोगों से कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे। जनगणना के दौरान कर्मचारियों द्वारा घर की स्थिति, संपत्ति, वाहन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। इसमें यह भी पूछा जाएगा कि घर किराये का है या स्वयं का, परिवार की आय कितनी है, घर में शौचालय है या नहीं, साइकिल, दोपहिया वाहन या कार है या नहीं। इसके अलावा फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाओं की

उपलब्धता से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जनगणना कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों के मानदेय (भत्ता) और अन्य आवश्यक प्रावधानों को शामिल करते हुए तमिलनाडु सरकार ने यह सरकारी आदेश जारी किया है, ताकि इस कार्य को सुचारु रूप से पूरा किया जा सके। इस बीच केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 की राष्ट्रीय जनगणना को दो चरणों में कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहला चरण राज्यों में निर्धारित समय के अनुसार कराया जाएगा, जबकि दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। देशभर में होने वाली इस जनगणना में लगभग 32 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। सरकार का मानना है कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार नई योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है, जिससे लोगों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुधार लाने में मदद मिलती है। इसलिए जब भी जनगणना से जुड़े सरकारी कर्मचारी घर पर आएं, तो उन्हें सही जानकारी देकर सहयोग करना चाहिए। यदि उस समय घर के सदस्य उपस्थित न हों तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कर्मचारी बाद में दोबारा भी आ सकते हैं।

# नगालैंड के मोकोकचुंग में मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

संवाददाता

**मोकोकचुंग।** नगालैंड के मोकोकचुंग जिले में वैज्ञानिकों ने मीठे पानी की मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज की है।

खास बात यह है कि इन दोनों प्रजातियों का नाम एक दिवंगत सहयोगी के बेटे और बेटी के नाम पर रखा गया है, जिससे उनकी अंतिम इच्छा पूरी

की गई। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नई खोजी गई प्रजातियों के नाम ग्लिप्टोथोरैक्स सेंटिमेरेनी और ओरेइचथिस एलियाने हैं। इनकी पहचान मोकोकचुंग जिले में किए गए इच्थियोलॉजिकल सर्वेक्षण के दौरान हुई। बाद में इस शोध को अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका जूटैक्सा में प्रकाशित किया गया।

# झांसी मंडल में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक

## एनएचएम योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के निर्देश

संवाददाता

**झांसी, उत्तर प्रदेश।** अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण झांसी मंडल डॉ. सुमन की अध्यक्षता में मंडलीय स्वास्थ्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रमों की लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अपर निदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित सभी योजनाओं में प्रगति लाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि होली और रमजान के अवसर पर बाहर काम करने वाले लोग अक्सर अपने गृह जनपद लौटते हैं। ऐसे में यदि उनके आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड नहीं बने हैं,

तो स्वास्थ्य कर्मी उनसे संपर्क कर उनके गोल्डन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके। बैठक में मातृ मृत्यु के मामलों की समीक्षा पर विशेष मंथन किया गया। इस दौरान हाई-रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों को समय से चिन्हित कर उनका समुचित उपचार सुनिश्चित कराने की रणनीति तैयार की गई, जिससे गर्भवती महिलाओं को संभावित जटिलताओं से बचाया जा सके। इसके साथ ही नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा अन्य जनस्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मंडलीय परियोजना प्रबंधक आनंद चौबे ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा कराई। इसमें उपलब्धियों, वित्तीय प्रगति तथा सुधार की आवश्यकता वाले बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 4D (जन्म दोष, रोग, कमी और विकास में विलंब) से ग्रसित बच्चों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि चिन्हित बच्चों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त बैठक में वित्तीय प्रगति, ओपीडी, आईपीडी और सर्जरी से संबंधित सेवाओं की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में मंडल के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस), स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न स्तरों के अधिकारी, प्रबंधक तथा विभिन्न कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

मालिक, प्रकाशक व मुद्रक- सुनील कुमार तिवारी द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट नं. ०४, ग्राउंड फ्लोर, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नियर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं ०२, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-४०००६३ से मुद्रित व ६१७, बिल्डिंग नं. १४ नियर शिव शक्ति बिल्डिंग, गोलीबार रोड, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुंबई-४०००५५ से प्रकाशित। **संपादक सुनील कुमार तिवारी,** RNI. NO. MAHMUL/2017/74054, **संपादकीय कार्यालयः कंटेश्वर सिंह चाल, अपोजीट एकताड़ मंडल, साईं बाबा रोड, खार (पूर्व), मुंबई- 400051, Mob. 8898271111**